

मोदी अपने मंत्रिमण्डल में फेरबदल शीघ्र ही करेंगे?

“ड्रीम टीम” बनाने का प्रयास है, कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनावों के पहले

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 मई। जैसे-जैसे राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सत्ता के गलियारों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि देश जल्द ही एक "ड्रीम टीम" को देख सकता है, जिसमें कुछ नए चेहरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रमुख भूमिकाएं निभा सकते हैं।
इन घटनाक्रमों के बीच, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि केरल से कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर को विदेश मंत्री जैसे हाई-प्रोफाइल पद की पेशकश की जा सकती है। यह नामांकन कथित तौर पर टेबल पर शुरु हो गया है, हालांकि इसका विवरण सामने नहीं आया है। लेकिन इन अटकलों ने पहले से ही आंतरिक संघर्ष और नीति-संबंधी पहचान के संकेत से जुड़ा रही कांग्रेस पार्टी में हलचल मचा दी है।

- चर्चाओं के अनुसार, अपनी पार्टी में अनदेखी से क्षुब्ध कई कांग्रेस के नेताओं को भी मोदी अपनी टीम में लेना चाहते हैं।
- “ड्रीम टीम” में शशि थरूर को भी विदेश मंत्री का पद ऑफर हो सकता है। कांग्रेस में काफी बेचैनी है, इस “ऑफर” की संभावना से।
- सलमान खुशीद व मनीष तिवाड़ी भी उन नेताओं के नामों की सूची में काफी ऊपर हैं, जो पार्टी के मत से भिन्न अपना मत रखते हैं। क्या मोदी इन नेताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से करीब-करीब भाजपा की नीति का समर्थन व्यक्त करने, का भी राजनीति लाभ उठावेंगे।
- उदाहरण के लिए, मनीष तिवाड़ी का नाम कांग्रेस ने अपनी सूची में नहीं रखा था, पर, मोदी ने उन्हें भी भारत के “ऑपरेशन सिंदूर” को समझाने के लिए, विदेशों में भेजे गए प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया है, और, चर्चाओं के अनुसार, मनीष तिवाड़ी ने ऑफर स्वीकार करने के बारे में अपनी स्वीकृति भी दे दी है।
- सलमान खुशीद ने भी हाल ही में इंडोनेशिया यात्रा के दौरान आर्टिकल 370 को रद्द करने के निर्णय को सही बताया, तथा कश्मीर के विधान सभा चुनाव में 65 प्रतिशत वोट पड़ने को सराहनीय बात बतायी। उनकी इस टिप्पणियों से भी कांग्रेस क्षुब्ध है, तथा भाजपा प्रसन्न।

थरूर द्वारा हाल ही में विवादस्पद "ऑपरेशन सिंदूर" का सार्वजनिक समर्थन किया, जो कि एक सांस्कृतिक

संपर्क अभियान है और जिसे कांग्रेस नेता बिहार चुनावों से पहले भाजपा की सांप्रदायिक वोट-बैंक रणनीति के

हिस्से के रूप में देखते हैं। थरूर के बयान ने पार्टी के भीतर दरार को और गहरा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

“हम पहलगाम की घटना के पहले की स्थिति में लगभग आ गये हैं”

पाकिस्तान के वरिष्ठतम सेना अधिकारी, जो पकिस्तान के, चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी हैं, ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यूज एजेन्सी “रॉयटर” को दिये गये इन्टरव्यू में यह दावा दिया

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 30 मई। इस्लामाबाद ने दावा किया है कि दोनों ही पक्ष अपनी सीमा पर सेना के जमावड़े को कम करके उसी स्तर पर ले जाने के नजदीक हैं, जिस स्तर पर इस माह दोनों पड़ोसियों के बीच संघर्ष छिड़ने से पहले था। लेकिन भारत ने इस मुद्दे पर खामोश बने रहना बेहतर समझा है।
जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जो पाकिस्तान जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन हैं, ने कहा कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, दोनों पक्षों की सेनाओं ने सीमा पर सैनिकों की संख्या कम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
दोनों पक्षों ने पिछले दशकों की सबसे प्रचंड लड़ाई के उन चार दिनों में फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन तथा

- जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने अपने इन्टरव्यू में यह भी कहा कि, 22 अप्रैल की स्थिति तक पहुंच ही गये हैं, और धीरे-धीरे दोनों सेनाएं अपने जवानों का पीछे हटाने का कार्यक्रम जारी करे हुए हैं और हम शीघ्र ही 22 अप्रैल के पहले की स्थिति में शीघ्र पहुंच जायेंगे।
- भारत ने जनरल साहिर रायशाद मिर्जा के दावे को अभी चैलेंज नहीं किया और न ही प्रतिक्रिया व्यक्त की।

आर्टिलरी को काम में लिया था और फिर चार दिन बाद, युद्धविराम की घोषणा हो गई थी।
परमाणु शक्ति संपन्न इन दोनों पुराने दुश्मनों के बीच हुई इस लड़ाई की शुरुआत 22 अप्रैल को कश्मीर में हुए उस आतंकी हमले से हुई, जिसमें 26 लोग मारे गये थे। इनमें ज्यादातर पर्यटक थे। नई दिल्ली ने इस घटना के लिए

पाक-समर्थित “आतंकियों” को जिम्मेवार ठहराया था। इस्लामाबाद ने भारत के इस आरोप का खंडन किया था।
सात मई को, भारत ने सीमा पार के “आतंकियों” के ठिकानों” पर मिसाइलें दागी थीं तथा पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए थे। दोनों देशों ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘नीट पीजी परीक्षा एक ही पाली में कराएं’

नयी दिल्ली, 30 मई। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 15 जून से होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी) 2025 दो की बजाय एक ही पाली में आयोजित कराने का शुक्रवार को निर्देश दिया।

- सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को यह निर्देश दिया। साथ ही कहा कि इसके लिए आवश्यक प्रबंध हेतु वे परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने का आवेदन कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजगिर्या की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने याचिकाकर्ता अदिति और अन्य की याचिका पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस नीट पीजी को आयोजित करने वाली संस्था नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) यह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

समरावता उपद्रव प्रकरण में नरेश मीणा को जमानत नहीं

जयपुर, 30 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थपड़ मारने के बाद समरावता में हुए उपद्रव प्रकरण में आरोपी नरेश मीणा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस प्रवीर

- देवली-उनियारा विधानसभा उपचनाव के दौरान व बाद में हुए उपद्रव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा पर कई मामले दर्ज हुए थे। तथापि, एस. डी. एम. को थपड़ मारने के मामले में मीणा को राहत मिली है।

भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश नरेश मीणा की द्वितीय जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए। दूसरी ओर जस्टिस अजित उपमन ने थपड़ कांड में मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
जस्टिस प्रवीर भटनागर ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अदालत ने गत 14 फरवरी को याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद केस की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स के एक्सपैंशन को लेकर राजनीति काफी गरम है

आंध्र प्रदेश चाहता है, यह “एक्सपैंशन” अब कर्नाटक के बजाय आंध्र में हो, जबकि कर्नाटक की सभी पार्टियों की इस बारे में एक राय है, कि, ‘एक्सपैंशन प्रोजेक्ट’ कर्नाटक के बाहर जाने का मतलब नहीं है।

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 मई। आंध्र प्रदेश, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के विस्तार कार्यक्रम को अपने राज्य में स्थानांतरित कराने की बड़ी कोशिश कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की यह कम्पनी दशकों पहले पड़ोसी राज्य कर्नाटक में स्थापित की गई थी। बोते छह महीनों से यह परियोजना काफी चर्चा में रही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस परियोजना के कुछ हिस्सों को आंध्र में स्थापित करना चाहते हैं। वह विमान क्षेत्र को एक प्रमुख उद्योग और रोजगार सृजन के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखते हैं।

स्वाभाविक रूप से इस प्रस्ताव ने कर्नाटक में भी भारी राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है, जहां सभी राजनीतिक दल इस संस्था को पूरी तरह राज्य में बनाए रखने के पक्ष में हैं और किसी भी हिस्से को किसी अन्य राज्य को देने के सख्त खिलाफ हैं। कर्नाटक में सत्तारूढ़ पार्टी होने के कारण, कांग्रेस इस पर काफी चिंतित है, उसे लगता है कि केन्द्र सरकार राजनीतिक मजबूरियों के चलते आंध्र प्रदेश को प्राथमिकता दे सकती है, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) केन्द्र में उसकी एक अहम सहयोगी है।
समझा जाता है कि हाल ही में चंद्रबाबू नायडू और नीति आयोग की बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र की इस प्रमुख कंपनी के कुछ कार्यों को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित करने का उनका अनुरोध कर्नाटक में चिंता का कारण बन गया है।

- पर, कर्नाटक को भय है, कि वह लड़ाई हारेगा, क्योंकि, मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू के समर्थन पर ही केन्द्रीय सरकार टिकी हुई है, अतः कोई आश्चर्य की बात नहीं कि केन्द्रीय सरकार, ‘एक्सपैंशन प्रोजेक्ट’ को आंध्र शिफ्ट कर दे।

को देने के सख्त खिलाफ हैं। कर्नाटक में सत्तारूढ़ पार्टी होने के कारण, कांग्रेस इस पर काफी चिंतित है, उसे लगता है कि केन्द्र सरकार राजनीतिक मजबूरियों के चलते आंध्र प्रदेश को प्राथमिकता दे सकती है, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) केन्द्र में उसकी एक अहम सहयोगी है।
समझा जाता है कि हाल ही में चंद्रबाबू नायडू और नीति आयोग की बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र की इस प्रमुख कंपनी के कुछ कार्यों को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित करने का उनका अनुरोध कर्नाटक में चिंता का कारण बन गया है।
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस अनुरोध का तीव्र विरोध किया और इस तरह के आडिडिया मात्र की भी आलोचना की।
और केवल उपमुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल सहित कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों ने भी इस अनुरोध की कड़ी निंदा की।
डी.के. शिवकुमार ने कहा, बंगलुरु एचएएल का मुख्यालय है और यह राज्य का औद्योगिक गौरव है और इसे स्थानांतरित करने की मांग संशोधन लौकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। उद्योग मंत्री पाटिल ने भी इस विचार

विरोध करने से कांग्रेस की स्थिति बड़ी हास्यास्पद हो गई। जबकि ज्यादातर विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को तुल नहीं दिया।
उधर, ममता बनर्जी ने जब सरकार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पहलगाम आतंकी हमले के शहीद शुभम के परिजनों से मिले प्र.मंत्री

कानपुर, 30 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कानपुर के चक्रेरी एयरपोर्ट पर पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की।

- प्र.मंत्री मोदी ने कानपुर के चक्रेरी हवाई अड्डे पर शुभम के माता-पिता व पत्नी से मुलाकात की और उन्हें ढांडस बंधाया।

कानपुर को विकास परियोजनाओं की सौगात देने पहुंचे मोदी ने एयरपोर्ट पर ही शुभम की पत्नी ऐशना, मां सीमा और पिता संजय द्विवेदी से करीब आठ मिनट तक बातचीत की।
शुभम के चाचा मनोज द्विवेदी ने बताया कि मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री भावुक हो गए इस दौरान (शेष अंतिम पृष्ठ पर)